WUEGA का अधनियिमन: महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम

यह एडटिोरियिल 04/03/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशति "A women's urban employment guarantee act" लेख पर आधारति है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (WUEGA) की संभावना पर वचिार कयिा गया है।

प्रलिमि्स के लयि:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम (MGNREGA), बेरोज़गारी दर, आवधकि श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना (AUEGS), मुख्यमंत्री शहरी आजीवकिा गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीवकिा मशिन (DAY-NULM), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनरि्भर नधि (PM SVANidhi)।

मेन्स के लयि:

महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (WUEGA) - आवश्यकता एवं संभावति चुनौतयिाँ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-MGNREGA) अकुशल शारीरकि कार्य के लयि प्रतविर्ष कम से कम 100 दनिों के रोज़गार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महलिाओं को वतितीय स्वायत्तता प्रदान करने में सहायक रहा है। हालाँकि इसकी शहरी वास्तवकिताएँ भनि्न हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधकि है, जो शहरी महलिाओं के बीच रोज़गार की उच्च अपूर्ण मांग को दर्शाती है। इस परदिृश्य में, भारत में महलिाओं के बीच शहरी बेरोज़गारी की चुनौतयिों का समाधान करने के लयि एक राष्ट्रीय **महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA)** का प्रस्ताव कयिा गया है।

प्रस्तावति महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (WUEGA):

- **परचिय:** महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (WUEGA) एक प्रस्तावति वधिान है जसिका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, वशिेष रूप से महलिाओं के लयि, संबोधति करना है। यह वशिेष रूप से शहरी महलिाओं के लयि रोज़गार के अवसरों की गारंटी देने की मंशा रखता है।
- **उद्देश्य:** WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुषों और महलिाओं के बीच रोज़गार के अवसरों में अंतराल को दूर करना होगा। WUEGA एक सुरक्षा जाल (safety net) और आय सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महलिाओं को सशक्त बनाने और शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहति करने का प्रयास करेगा।
- **संभावति वशिेषताएँ:**
    - **रोज़गार की गारंटी:** WUEGA महलिाओं को **प्रतविर्ष न्यूनतम कार्यदविस (उदाहरण के लयि, 150 दनि) की गारंटी देने का प्रस्ताव** करता है।
    - **स्थानीय कार्य:** महलिा के नवािस से उचति दूरी (जैसे, 5 कमिी) के भीतर कार्य अवसर सृजति कयि जाएँगे।
    - **अभगिम्य अवसंरचना:** कामकाजी माताओं के समक्ष वद्यिमान चुनौतयिों का समाधान करने के लयि कार्यस्थलों पर बाल देखभाल केंद्रों जैसी आवश्यक सुवधिाओं के प्रावधान भी शामलि हो सकते हैं।
    - **कौशल वकिास:** प्रस्ताव में उपलब्ध कार्य अवसरों और आवेदक समूह में महलिाओं की योग्यता के बीच कसिी भी कौशल अंतराल को दूर करने के लयि प्रशकि्षण कार्यक्रम भी शामलि हो सकते हैं।
    - **महलिा-नेतृत्वकारी प्रबंधन:** यह प्रस्ताव करता है कि WUEGA प्रबंधन कर्मचारयिों में एक उल्लेखनीय भाग महलिाओं का हो; WUEGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी की **कम से कम 50% (आदर्श रूप से 100%) महलिाएँ हो।**
    - **समर्थनकारी उपाय:** कल्याण बोर्डों में स्वचालति समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाये जा सकते हैं; ये मातृत्व अधकिार और पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसयिों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा आपातकालीन नधिि के लयि स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (WUEGA) की आवश्यकता क्यों है?

- **शहरी रोज़गार में लैंगकि असमानताएँ:**

- **शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में प्रायः** लिंग-आधारित असमानताएँ देखी जाती हैं। [आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)](#) के अनुसार, **वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में केवल 22.9%** शहरी महिलाएँ ही कार्यरत थीं।
    - शहरी क्षेत्रों में कार्यबल से बाहर **मौजूद महिलाओं (15-59 आयु वर्ग) की संख्या लगभग 10.18 करोड़** है।
- मौजूदा शहरी रोज़गार योजनाएँ महिलाओं के समक्ष विद्यमान इन विशिष्ट चुनौतियों को उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।

- **आर्थिक सशक्तीकरण और सतत विकास लक्ष्य:**
    - WUEGA शहरी महिलाओं को गारंटीकृत रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्यदिवस सुनिश्चित करने से यह महिलाओं को अपने घरों और समुदायों में योगदान कर सकने में सक्षम बनाता है।
    - लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
- **बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचना:**
    - शहरी महिलाओं के बीच शिक्षा के उच्च स्तर के बावजूद सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा चिंताओं और परिवहन तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है।
    - WUEGA कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देता है । ये प्रावधान महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों से समझौता किये बिना रोज़गार में भाग ले सकने में सक्षम बनाते हैं।
- **सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से सबक लेना:**
    - WUEGA मनरेगा (MGNREGA) जैसी सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भों के लिये सदृश मॉडल को अपना सकता है।
    - WUEGA मौजूदा ढाँचे और अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये सिद्ध रणनीतियों का निर्माण कर सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावना:**
    - महिलाओं की रोज़गार दर में वृद्धि श्रम शक्ति का विस्तार और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के रूप में आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
    - WUEGA में शहरी महिलाओं की प्रतिभा एवं सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान कर सकने की क्षमता है।

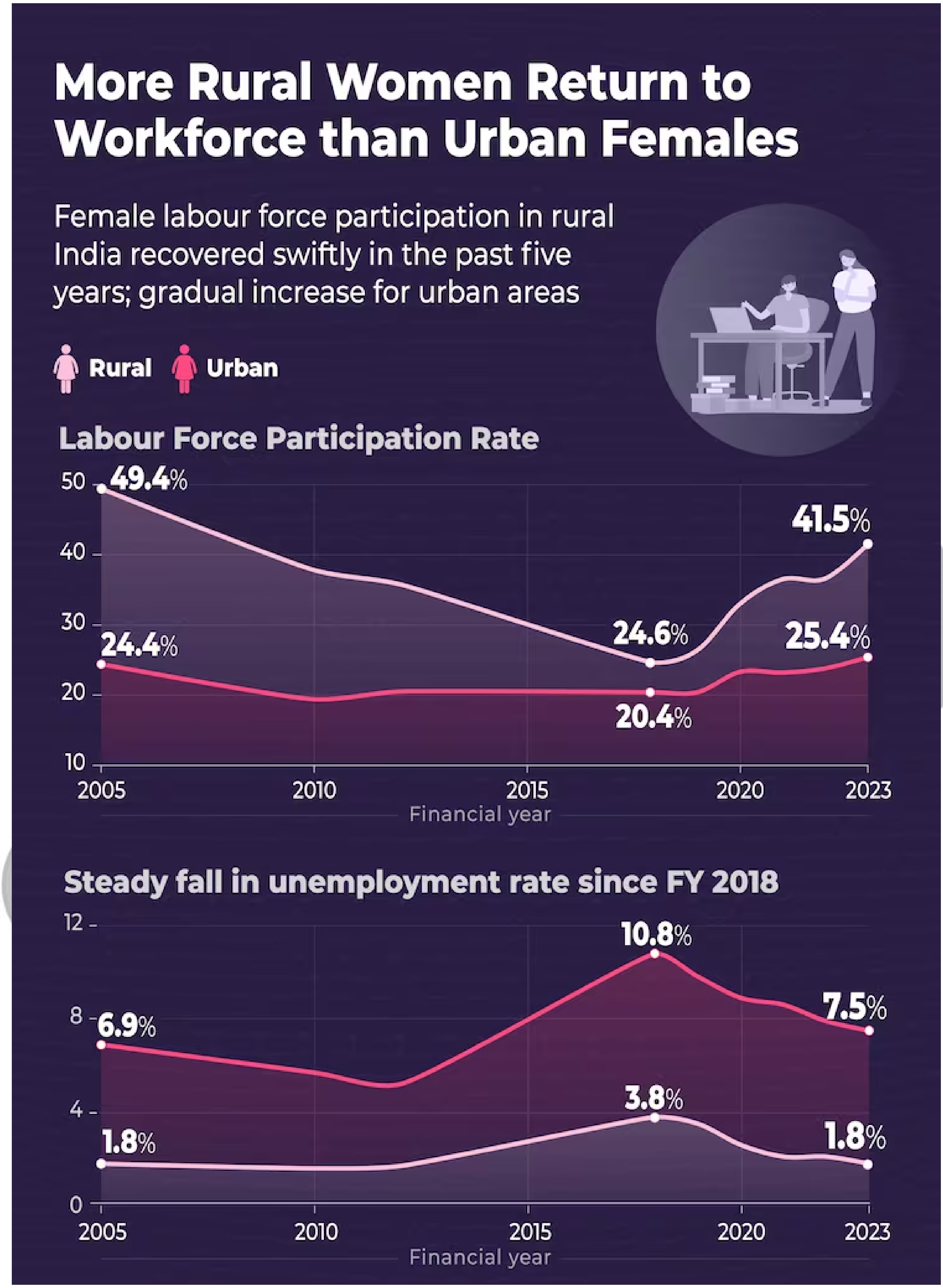

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावित चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बोझ:**
  - गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना विकास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएँ) और

कार्यक्रम प्रशासन के संबंध में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लयि, यदि 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रतिवर्ष 150 दनिों के कार्य की कल्पना करें, जसिका वित्तिपोषण केंद्र सरकार द्वारा कयिा जाना है, तो इस पर [सकल घरेलू उत्पाद]() का लगभग 1.5% व्यय करना होगा।
- **स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार सृजन:**
  - कसिी महलिा के नविास से उचति दूरी (उदाहरण के लयि, 5 कमी) के भीतर पर्याप्त वविधि कार्य अवसर का सृजन करना, वशिष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूर्ण सदि्ध हो सकता है।
  - कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य वकिल्पों की अभकिल्पना के लयि स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत संरचनाओं पर वचिार करने की आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा संबंधी चताएँ:**
  - शहरी परविश में महलिाओं के लयि, वशिष रूप से कार्य के लयि आवागमन के दौरान, सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण चतिा का वषिय है।
  - सार्वजनकि स्थानों पर उत्पीड़न या हसिा का भय महलिाओं को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहति कर सकता है, जसिसे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमति हो सकती है।
  - NCRB की **वार्षकि अपराध रपिोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रतिएक लाख जनसंख्या** पर महलिाओं के वरिुद्ध अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखलि करने की दर 75.8 दर्ज की गई थी।
- **कौशल अंतराल:**
  - कई शहरी महलिाओं में औपचारकि रोज़गार के अवसरों के लयि आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
  - गुणवत्तापूर्ण शक्षिा और व्यावसायकि प्रशक्षिण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमति हो सकती है, जसिसे कौशल स्तरों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं और महलिाओं की रोज़गार क्षमता (employability) में बाधा आ सकती है।
- **क्षमता नरि्माण:**
  - सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में कम से कम 50% महलिाओं की उपस्थिति सुनशि्चति करना आरंभ में कठनि सदि्ध हो सकता है।
  - कार्यक्रम के प्रबंधन के लयि एक सुदृढ़ महलिा कार्यबल के नरि्माण के लयि केंद्रति क्षमता-नरि्माण पहल की आवश्यकता हो सकती है।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:**
  - कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लयि पंजीकरण, नौकरी आवंटन, शकियत नवािरण एवं नगिरानी के प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थति नौकरशाही की आवश्यकता होगी।
  - ऐसे व्यक्तयिों या समूहों द्वारा वरिोध की स्थिति बन सकती है जो परविर्तन के प्रतरिोधी हैं और यथास्थिति बनाए रखने की वकालत करते हैं। यह महलिाओं के रोज़गार अधकिारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारति होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजकि मानदंड और लैंगकि रूढ़वािदता:**
  - गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजकि अपेक्षाएँ कार्यबल में महलिाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, वशिष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ पारंपरकि लगि भूमकिाएँ अधकि प्रकट हैं।
  - देखभालकर्ता या गृहणिी के रूप में महलिाओं की भूमकिाओं के संबंध में प्रचलति रूढ़वािदति औपचारकि रोज़गार में उनकी भागीदारी के लयि प्रतरिोध पैदा कर सकती है।

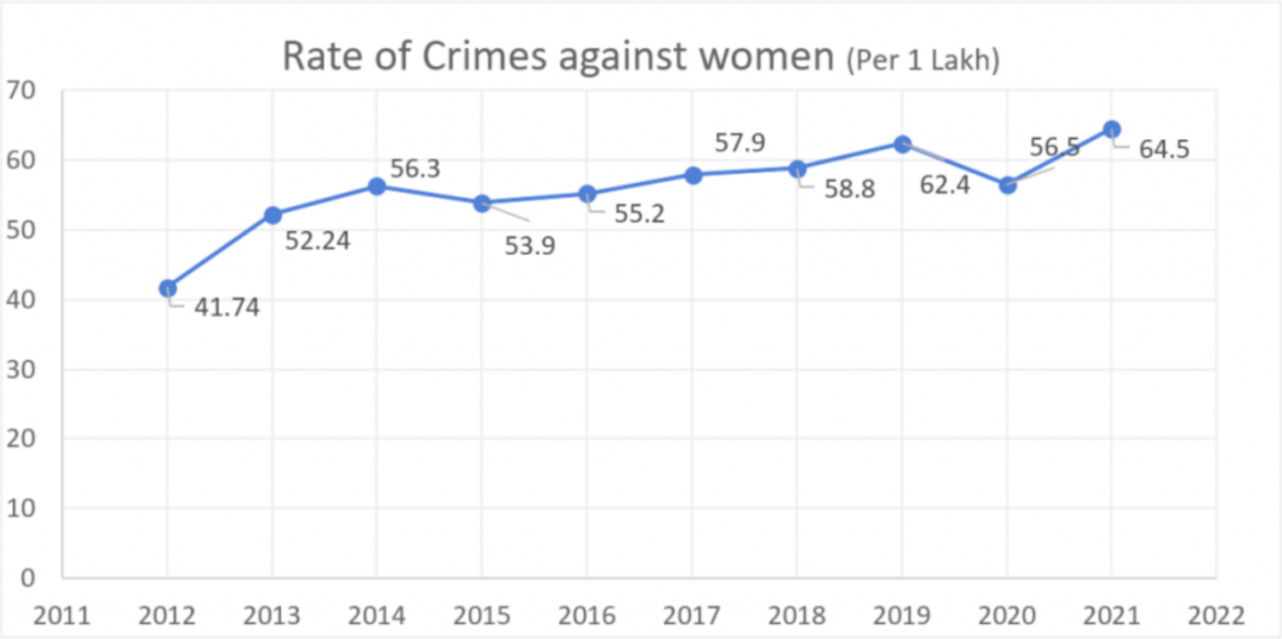

भारत में शहरी रोज़गार के लयि की गई सरकारी पहलें:

- **केंद्र सरकार द्वारा:**
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM)
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनर्भिर नधि(पीएम SVANidhi)
- **राज्य सरकारों द्वारा:**
  - **केरल** देश के पहले राज्यों में से एक था जसिने **'अय्यंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme- AUEGS)** के माध्यम से 100 व्यक्ति-दविस का गारंटीकृत वेतन रोज़गार प्रदान कयिा था, जसि वर्ष 2011 में लॉन्च कयिा गया था। योजना दशिानरि्देशों के अनुसार केरल में शहरी स्थानीय नकियों (ULBs) को महलिाओं को इस प्रकार प्राथमकिता देने की आवश्यकता है कि वे योजना के लाभार्थयिों में कम से कम 50% हस्सिदारी रखती हों।
  - **हमिाचल प्रदेश** की **मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वत्तिीय वर्ष में प्रत्येक परवािर को 120 दनिों की गारंटीकृत वेतन रोज़गार प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीवकिा सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षति है।
  - **झारखंड** में **मुख्यमंत्री श्रमकि योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वत्तिीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दनि का वेतन रोज़गार प्रदान कर राज्य में आजीवकिा सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षति है।

WUEGA के प्रभावी अधनियिमन के लयि आगे की राह:

- **लगि-वभिदीकृत डेटा एकत्रति करना:**
  - लगि-वभिदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीतनिरि्माताओं को शहरी महलिाओं के समक्ष रोज़गार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में वद्यिमान वशिष्टि चुनौतयिों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टप्रिदान करता है।
  - संग्रहति डेटा में पसंद की जाती नौकरयिों के रुझान, वर्ष के वे दनि जब महलिाएँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महलिाओं की शक्षिा का स्तर इत्यादकिो दर्ज कयिा जाना चाहयि।
- **लैंगकि दृष्टसि शहरी रोज़गार योजना तैयार करना:**
  - महलिा शहरी रोज़गार गारंटी अधनियिम (डब्ल्यूयूईजीए) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपति कयिा जाए, जो लगि-वभिदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्राप्तकर्ताओं दोनों के अधकिारों, वशिषाधकिारों एवं उत्तरदायत्विों को नरिूपति करता हो।
  - वधिान में समान कार्य के लयि समान वेतन अनवािर्य कयिा जाना चाहयि, जहाँ यह सुनश्चिति करना चाहयि कमिहलिाओं को समान कार्य भूमकिाओं एवं ज़म्मिदारयिों के लयि अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त हो।
- **संसाधन आवंटन और क्षमता नरि्माण:**
  - WUEGA के कार्यान्वयन के लयि पर्याप्त वत्तिीय संसाधन आवंटति कयिा जाए ताकवितन, प्रशासनकि व्यय, अवसंरचना वकिास और क्षमता नरि्माण पहल के लयि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
  - WUEGA के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को सुनश्चिति करने के लयि सरकारी अधकिारयिों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थयिों के लयि प्रशक्षिण एवं क्षमता नरि्माण कार्यक्रम प्रदान कयि जाएँ।
- **कार्यान्वयन के लयि चरणबद्ध दृष्टकिोण:**
  - WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लयि चुनदाि शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू कयि जाएँ। वभिन्नि शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावति चुनौतयिों एवं अवसरों की पहचान करने के लयि व्यवहार्यता अध्ययन आयोजति कयि जाएँ।
  - WUEGA का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू कयिा जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालयिाँ अपेक्षाकृत सुवकिसति होती हैं और फरि धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में वस्तिारति कयिा जाए।
- **कार्यान्वयन की प्रगतकिी नगिरानी करना:**
  - रोज़गार सृजन, आय वृद्धऔिर कौशल वकिास जैसे परणिामों पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन की प्रगतकिी नगिरानी करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लयि सुदृढ़ नगिरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापति कयि जाएँ।
- **सुरक्षा संबंधी चताओं का समाधान करना:**
  - सुरक्षा चताओं को कम करने और अधकि कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहति करने के लयि सार्वजनकि स्थानों पर महलिाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू कयि जाएँ, जनिमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, नगिरानी प्रणाली एवं पुलसि गश्त बढ़ाना शामलि है।
- **महलिा उद्यमयिों का समर्थन करना:**
  - महलिा उद्यमयिों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लयि सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान कयिा जाए, जसिमें वत्तिीय संसाधनों, परामर्श कार्यक्रमों एवं नेटवर्कगि अवसरों तक पहुँच शामलि है, ताकरिोज़गार और आर्थकि सशक्तीकरण के लयि वैकल्पकि अवसर सृजति कयि जा सकें।
- **साझेदारी और सहयोग:**
  - नागरकि समाज संगठनों, सामुदायकि समूहों, नजिी क्षेत्र के हतिधारकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसयिों के साथ साझेदारी का नरि्माण कयिा जाए।
- **जागरूकता बढ़ाना और दृष्टकिोण में बदलाव लाना:**
  - लैंगकि रूढ़वादिता को चुनौती देने, लैंगकि समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महलिाओं की भूमकिाओं एवं क्षमताओं के प्रतसिामाजकि दृष्टकिोण को बदलने के लयि जागरूकता अभयिान एवं संवेदीकरण कार्यक्रम संचालति कयि जाएँ।

नष्किर्ष:

भारत का संवधािन समानता एवं सामाजकि न्याय के सद्धिांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोज़गार में लैंगकि असमानताओं को दूर करने के लयि सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध कयिा गया है। WUEGA को लागू करना लैंगकि समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवैधानकि अधदिशों एवं और नैतकि दायत्विों के अनुरूप है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता और आगे की राह की संभावति बाधाओं पर वचिार कीजयिे। देश में महिलाओं के प्रभावी आर्थकि सशक्तीकरण हेतु आवश्यक रणनीतियाँ बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन ग्रामीण क्षेत्रीय नर्धिनों के आजीवकिा वकिल्पों को सुधारने का कसि प्रकार प्रयास करता है? (2012)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए वनिर्मिाण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापति कर।
2. 'स्व-सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल वकिास की सुवधिाएँ प्रदान कर।
3. कृषकों को नःिशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पंपसेट तथा लघु सचिाई सयंत्र देकर।

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्र. भारत में महलिाओं की सशक्तीकरण प्रक्रयिा में 'गगि इकोनॉमी' की भूमकिा का परीक्षण कीजयिे। (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/enact-wuega-women-s-urban-employment-guarantee-act